हैदराबाद में टीन के डिब्बों में बन्द फलों के रस का कारखाना

२५७२. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि टीन के डिब्बों में बन्द फलों के रस के लिये हैदराबाद में एक कारखाना बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब, किसकी सहायता से और उस पर कितना खर्च होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) कारखाने का भवन तैयार हो रहा है । यह पता नहीं कि वह कब तक पूरा हो जायेगा । पता चला है कि इस कारखाने के लिये हंगरी के कोमपलेक्स नामक एक उद्योग से लगभग ४ लाख रुपये की लागत की मशीनों का आयात हुआ है । इस बात का भी पता नहीं है कि इस कारखाने पर कुल कितना रुपया व्यय होने की संभावना है ।

निजामाबाद रेलवे स्टेशन

२५७३. **श्री रामसेवक यादव :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें निजामाबाद के बीड़ी निर्माता तथा तम्बाकू व्यापारी संघ से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर दैनिक बुकिंग की सुविधा की व्यवस्था की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) माल गोदाम में अस्थायी तौर पर बहुत अधिक माल जमा हो जाने के कारण बुकिंग के लिए प्रति दिन माल लेने में कुछ कठिनाई हो गयी थी । जमा माल निकाल दिया गया है और बुकिंग के लिये अब माल प्रतिदिन लिया जा रहा है ।

Rehabilitation of displaced persons from Haldia Port

2574. **Shri S. C. Samanta:**
Shri Subodh Hansda:
Shri B. K. Das:
Shri P. C. Barman:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) how far the development work of the 200 acres of land for the rehabilitation of the displaced persons from Haldia Port site has progressed;

(b) how the development cost is going to be met;

(c) when the land is expected to be ready for distribution; and

(d) whether tube-wells, schools, markets and other necessary facilities will be available there?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) to (d). It has been ascertained from the State Government who are making the necessary arrangements that out of about 1800 plots to be provided for housing purposes, about 400 plots will be ready by the end of this month.

The total cost of development of the rehabilitation site has been assessed at Rs. 8,30,700. The Calcutta Port Commissioners have agreed to share the cost on a 50:50 basis with the West Bengal Government.

The State Government have stated that a layout plan for the rehabilitation scheme has been drawn up and that sufficient land has been set apart for tanks, roads, parks, playgrounds, schools, markets, health centres etc. Steps are being taken by the State Government to sink a number of tubewells in the area.